राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 112

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, सोमवार, 30 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

मुख्य कोच रवि शास्त्री को दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है

>> 12

सरोकार

बेजोड़ है प्राथमिक शिक्षा का बलिया मॉडल

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं एक बारगी

कान्वेंट स्कूल से भी बेहतर दिखती हैं। प्रधानाध्यापक उमेश सिंह के प्रयासों से बलिया जिले के नवीन प्राथमिक विद्यालय करमपुर में बुनियादी शिक्षा का ऐसा वातावरण बना है, जो दूसरों के लिए आदर्श है। (पेज-13)

जागरण विशेष

विरासत के पाले में कबड्डी की परंपरा

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का जिक्र किए बिना खेलों की बात अधूरी है।

जिले के फखरपुर और बसी गांव के युवाओं को तो यह खेल विरासत में मिला है। बेटों के साथ बेटियों के दिन की शुरुआत भी कबड्डी की सीटी सुनकर ही होती है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी

मुंबई : कांग्रेस ने महाराष्ट्र विस चुनाव के लिए रविवार को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस-राकांपा पहले ही 124-124 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं, शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन की घोषणा से पहले ही कई नेताओं को पर्चा भरने के लिए जरूरी एबी फॉर्म बांट दिए हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

राजस्थान में डोडा-पोस्त के धंधे में लिप्त हैं कई नेता-अफसर

जयपुर : राजस्थान में डोडा-पोस्त की पंजाब और अन्य राज्यों में तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में डोडा-पोस्त के अवैध कारोबार को जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों ने जमकर संरक्षण दिया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

भारत में सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा सऊदी अरब

नई दिल्ली : दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर (करीब सात लाख करोड़ रुपये) का निवेश करेगा। यह निवेश मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और खनन समेत कई अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। भारत में सऊदी अरब के राजदूत डॉ. सऊद बिन मुहम्मद अल सती ने कहा, उनके देश के लिए भारत बेहद आकर्षक निवेश बाजार है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

हांगकांग में फैली हिंसा, कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े लोग

हांगकांग : हांगकांग में रविवार को पूरे दिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव होता रहा। कई स्थानों पर भड़के विरोध प्रदर्शनों को जब पुलिस ने पानी की बौछार, रबर बुलेट और आंसू गैस से काबू करने की कोशिश की तो उसे पेट्रोल बमों और पत्थरों से जवाब दिया गया। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर आने से पुलिस को लेने के देने पड़ गए।

युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगाया ई-सिगरेट पर प्रतिबंध : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ई-सिगरेट पर रोक युवाओं को नशे की इस नई लत से बचाने तथा परिवारों को तबाह होने से बचाने के लिए लगाई गई है। युवा फैशन के नाम पर इसके जाल में फंस जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात रविवार को 'मन की बात' में की। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम में जॉगिंग करते हुए कचरा बीनने के लिए चलाए गए 'प्लॉगिंग' अभियान की भी सराहना की।

सरकार ने हाल में ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध का एलान किया है। इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि ई-सिगरेट के बारे में यह भ्रांति फैलाई गई है कि इससे कोई खतरा नहीं है। सच यह है कि इसमें कई हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। फैशन के चक्कर में युवा इसके जाल में फंसकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध जरूरी था।

मोदी ने दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के संकल्प की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिस प्रकार भारत ने दुनिया में बढ़त ली है, उससे सभी देशों की नजरें हमारी ओर टिकी हैं। देश के एक नौजवान रिपुदमन बेल्वी ने अनोखा 'प्लागिंग' अभियान चलाया है। जिसमें कसरत के साथ-साथ सफाई भी हो जाती है। जॉगिंग पर निकले लोग रास्ते में पड़ा कचरा भी हटाते जाते हैं। मोदी ने सभी देशवासियों से इसका हिस्सा बनने व देश को स्वच्छ बनाने में योगदान करने को कहा। मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता एवं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के लिए 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ में शामिल होने की भी सभी लोगों से अपील की।

बांटने से बढ़ती हैं खुशियां : देशवासियों को नवरात्र और त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने कहा, इस बार सब लोग जरूरतमंदों के साथ अपने घर की अतिरिक्त वस्तुएं और खाने-पीने का सामान बांटकर त्योहार मनाएं तो सच्ची खुशियां हासिल होंगी। त्योहारों का असली आनंद तभी है जब सब ओर उजाला फैले।

करें घर की लक्ष्मी का सम्मान : मोदी ने समाज में उल्लेखनीय कार्य कर रही बेटियों, बहुओं को लक्ष्मी मानकर सम्मानित करने तथा उनकी उपलब्धियों को सोशल मीडिया में पहचान दिलाने के लिए 'भारतलक्ष्मी' हैशटैग के इस्तेमाल की सलाह भी दी। मोदी ने अरुणाचल की छात्रा अलीना तायंग के पत्र का जिक्र भी किया। इसमें अलीना ने प्रधानमंत्री से 'एक्जाम वारियर' पुस्तक का दूसरा संस्करण लिखने का अनुरोध किया है। मोदी ने कहा, वक्त मिला तो वह अवश्य ऐसा करेंगे।

दानील के मुरीद हुए पीएम : प्रधानमंत्री इस बार के यूएस ओपेन के रनर अप दानील मेदवेदेव की विनम्रता, सरलता और खेल भावना से अत्यंत प्रभावित दिखाई दिए। 'मन की बात' में उन्होंने कहा कि 23 साल के दानील की परिपक्वता हर किसी को प्रभावित करने वाली थी। कोई और होता तो उदास व निराश हो गया होता। परंतु उन्होंने अपनी बातों से सब के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सिस्टर मरियम थ्रेसिया को दी श्रद्धांजलि : पीएम ने होली फैमिली मिशन की संस्थापक सिस्टर मरियम थ्रेसिया को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें 13 अक्टूबर को वेटिकन सिटी में संत घोषित किया जाएगा। मोदी ने कहा कि पचास साल के छोटे से जीवनकाल में थ्रेसिया ने मानवता की भलाई के लिए जो कार्य किए, वे दुनिया के लिए मिसाल हैं। उन्होंने कई स्कूल, हॉस्टल और अनाथालय बनवाए और जीवनपर्यंत इस मिशन में लगी रहीं।

पर्यटन का हब बनेगा भारत : 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में मोदी ने पर्यटन के नक्शे में भारत की बढ़ती रैंकिंग का उल्लेख किया। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने संबोधन का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने लोगों से 2022 तक भारत के 15 स्थानों की सैर करने को कहा था। इस संबोधन की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा, 'भारत ने ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटीटिव इंडेक्स में बहुत सुधार किया है। आज हमारा 34वां स्थान है। पांच साल पहले हमारी रैंकिंग 65वीं थी। हमने और कोशिश की तो आजादी के 75 साल आते-आते टूरिज्म में दुनिया के प्रमुख स्थानों में जगह बना लेंगे।'

मन की बात

- फैशन के नाम पर नशे का शिकार हो रहे युवाओं पर जताई चिंता
- जॉगिंग के साथ कचरा बीनने के 'प्लॉगिंग' अभियान की सराहना की

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (आकाशवाणी के ट्विटर से)

मोदी के आने से बदल रहा है देश पेज>>3

कश्मीर में कहीं कोई पाबंदी नहीं : शाह

खरी-खरी ▶ कश्मीर समस्या को यूएन में ले जाना नेहरू की हिमालय से भी बड़ी भूल

कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संविधान सम्मत, विपक्ष फैला रहा भ्रम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सवाल उठा रहे लोगों, खासकर विपक्ष को करार जवाब दिया है। शाह ने रविवार को यहां कहा कि कश्मीर में कहीं कोई पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई के पहले गृहमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि इसे हटाने का फैसला पूरी तरह संविधान सम्मत है। कश्मीर समस्या के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए शाह ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में जाने को हिमालयी भूल से भी बड़ी गलती करार दिया।

तीन मूर्ति भवन में पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच की पांचवी व्याख्यान माला में शाह ने कहा, विपक्ष कश्मीर में प्रतिबंधों को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने सवाल किया, 'प्रतिबंध कहां है? यह आपके दिमाग में है। कहीं कोई पाबंदी नहीं है। प्रतिबंधों को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।' कश्मीर में सभी 196 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। सिर्फ आठ थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। लोग आजादी से कहीं भी आ जा रहे हैं। देश के दूसरे क्षेत्रों के पत्रकार भी कश्मीर बिना रोक-टोक आ रहे हैं।

इमरान खान को जवाब : शाह ने कश्मीर में कर्फ्यू को लेकर अपने बयान से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जवाब दे दिया है। इमरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि कश्मीर से जब कर्फ्यू हटाया जाएगा तब वहां खून खराबा होगा।

विकसित राज्य बनेगा कश्मीर : केंद्रीय गृह मंत्री ने घाटी में हालात पूरी सामान्य होने का दावा करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में विकास की नई बयार बहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले एक दशक में जम्मू-कश्मीर भारत का सबसे विकसित राज्य बनकर उभरेगा।

मानवाधिकार को लेकर साधा निशाना : अमित शाह ने कहा कि दशकों के आतंकवाद में 41,800 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन कोई भी जवानों, उनकी विधवाओं या अनाथ हुए उनके बच्चों के मानवाधिकारों की बात नहीं करता। परंतु, कुछ दिनों से मोबाइल सेवा बंद होने पर लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन कनेक्शन का नहीं होना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है। शाह ने कहा कि पिछले दो महीने में घाटी में 10 हजार नए लैंडलाइन कनेक्शन दिए गए हैं और छह हजार से ज्यादा पीसीओ खुले हैं।

सच्चा इतिहास लिखने का वक्त : कांग्रेस पर कश्मीर के इतिहास को तोड़-मरोड़कर जनता के सामने रखने का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने गलतियां की थी, इतिहास लिखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी और उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाया। शाह ने कहा कि 'अब समय आ गया है कि इतिहास सच्चा लिखा जाए और सच्ची जानकारी जनता को दी जाए।'

नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते अमित शाह। जागरण डॉट काम

राज्य में तहसील और जिला पंचायत के चुनावों की घोषणा चार से पांच दिनों के भीतर

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में तहसील और जिला पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा चार से पांच दिनों के भीतर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार वहां त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली पूरी तरह से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। शाह ने कहा कि राज्य के 40 हजार गांवों में ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन गांवों के विकास के लिए सरकार 70 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। ये पैसे सीधे ग्राम प्रधानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यह पैसा सचिवालय स्तर से नीचे तक पहुंचता ही नहीं था।

पूरा कश्मीर हमारा होता पेज>>3

पटना में अस्पताल-घरों में भरा पानी, सड़क पर चलीं नाव

- राजधानी पटना में शुक्रवार रात से अब तक 225 मिमी से ज्यादा बारिश

पटना के राजेंद्रनगर कॉलोनी में लोगों को घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाती एसडीआरएफ की टीम। जागरण

जागरण टीम, पटना

बारिश ने रविवार को भी पटना समेत पूरे बिहार में कहर बरपाया। मूसलधार बारिश से पानी घरों और अस्पताल में घुस गया है। छह-सात फीट तक जलभराव के चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पटना में जिला प्रशासन ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए डेढ़ दर्जन नावें चलाई हैं।

लगातार बारिश से उत्तर बिहार और कोसी-सीमांचल की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। तेज हवा से कई स्थानों पर पेड़ और घर गिरे हैं। बिजली आपूर्ति ठप रही। रेल, हवाई और बस सेवाएं प्रभावित हैं। बिहार के कई जिलों में सभी स्कूल मंगलवार तक बंद हैं। पटना विवि, मगध व पाटलिपुत्र विवि के कॉलेज भी सोमवार को बंद रहेंगे। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पटना में पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों की मांग की है।

अन्य जिलों में भी हालात बदतर : छपरा जिला प्रशासन ने बारिश को आपदा घोषित कर अफसरों-कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी है। छपरा- बलिया रेलखंड पर बांसडीह के बीच ट्रैक धंसने से आधा दर्जन ट्रेनों को सिवान-गोरखपुर के रास्ते निकाला गया। बरौनी-कटिहार खंड पर कई ट्रेनों को रद किया गया तो कई के रूट बदले गए। (पेज-7 पर)

बेअंत सिंह के हत्यारे की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया स्वागत, बादल भी लेते रहे हैं पक्ष

गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर मानवीय आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन नौ कैदियों को राहत दी है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल बब्बर खालसा का बलवंत सिंह राजोआणा भी शामिल है। उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी अभी राज्य सरकार को नहीं मिली है।

ज्ञात हो, चंडीगढ़ में सचिवालय के बाहर 31 अगस्त, 1995 को आतंकियों ने बेअंत सिंह की कार को बम से उड़ा दिया था। इस घटना में बेअंत समेत 16 लोगों की मौत हुई थी। पंजाब पुलिस के सिपाही दिलावर सिंह ने हमले में मानव बम की भूमिका निभाई थी, जबकि बलवंत सिंह राजोआणा ने हमले की साजिश रची थी। पकड़े जाने पर राजोआणा ने अपने बचाव में कोई वकील नहीं किया था और न ही फांसी कि सजा माफ करने की अपील की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने आठ सिख कैदियों की रिहाई और राजोआणा की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के फैसले का स्वागत किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी उसको फांसी देने के हक में नहीं रहे हैं। उन्होंने अपील की थी कि पंजाब में अमन, एकता और भाईचारा हर स्थिति में कायम रखने के लिए मामले में मानवीय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

पंजाब-हरियाणा की राजनीति पर असर डालेगा फैसला : केंद्र का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पंजाब के साथ दिल्ली और हरियाणा में भी असर डालेगा।

लालू के घर में गंभीर हुआ सास,ननद और बहू का झगड़ा

राज्य ब्यूरो, पटना

- बहू ऐश्वर्या को राबड़ी के घर से धक्के मारकर निकाला गया
- सास ने घर में आने से रोका तो माता-पिता संग ससुराल के सामने दिया धरना

पटना के महिला हेल्पलाइन में पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर पहुंची ऐश्वर्या (दाएं)। जागरण

लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने रविवार को सास राबड़ी देवी पर धक्के मारकर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। रविवार दोपहर एक बजे राबड़ी देवी के सरकारी आवास में हाईवोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

पहली बार मीडिया से मुखातिब ऐश्वर्या ने कहा कि पिछले तीन माह से मुझसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। यहां तक कि मेरा खाना भी बंद कर दिया गया है। खाना मेरे मायके से आता है। शनिवार से तो मेरा किचन में भी जाना बंद कर दिया गया। सास के कहने पर मुझे चाबी भी नहीं दी गई। जब मैं पूरी घटना रिकार्ड करने लगी तो उनके एक स्टाफ ने मेरा मोबाइल छीन लिया। ऐश्वर्या ने ननद व राज्यसभा सदस्य डॉ. मीसा भारती पर मारपीट करने के साथ ही लालू-राबड़ी परिवार पर और भी आरोप लगाए। मीसा ने आरोपों को खारिज करते हुए खुद के दिल्ली में होने का दावा किया। देर शाम ऐश्वर्या ने ससुराल लौटने की कोशिश की तो राबड़ी देवी ने खुद को खतरा बताते हुए बहू को घर में आने से रोक दिया। इसके बाद ऐश्वर्या माता-पिता के साथ धरने पर बैठ गईं। परिवार में यह ड्रामा तब हुआ जब तेजस्वी यादव तीन दिनों से दिल्ली में हैं।

मीसा नहीं बसने देना चाहतीं मेरा घर : ऐश्वर्या ने कहा,मीसा अक्सर ससुराल से निकल जाने के लिए दबाव बनाती हैं। कहती हैं कि तुम यहां रहोगी तो तेजप्रताप जहर खा लेगा। ऐश्वर्या बोलीं, शादी के बाद भी मीसा काफी समय से मायके में ही रह रही हैं। मीसा ही तेजप्रताप और तेजस्वी में दरार डाल रही हैं। ऐश्वर्या ने कहा, लोकसभा चुनाव में राजद की हार के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा।

लालू, तेजस्वी से नहीं शिकायत : ऐश्वर्या ने कहा, अगर वह (लालू) यहां होते तो चीजें ठीक कर देते। तेजस्वी यादव के लिए कहा कि उनका सहयोग मुझे मिलता रहता है। ऐश्वर्या के पिता एवं विधायक चंद्रिका राय ने सचिवालय थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञात हो, ऐश्वर्या और तेजप्रताप की शादी 2018 में 12 मई को हुई थी। दो नवंबर को तेजप्रताप ने पटना की अदालत में तलाक की अर्जी दे दी।

- मैं पति तेजप्रताप के साथ रिश्ते ठीक करना चाहती हूं। तलाक का केस फाइल होने के बाद भी उनके साथ रह रही हूं। लेकिन ससुराल में ऐसे व्यवहार किया जाता है, जैसे हमारा तलाक हो चुका है। **-ऐश्वर्या राय**
- जब मैं पटना में रहती ही नहीं हूं तो चाबी कैसे छीन सकती हूं। सास-बहू की लड़ाई में अक्सर ननद को भी घसीटा जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। **-मीसा भारती**
- लालू परिवार से रिश्ते की बात पर अब शर्म महसूस होती है। मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि ये लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी यहां नहीं करता। **-चंद्रिका राय, ऐश्वर्या के पिता**
- हमें दामाद तेजप्रताप यादव से मिलने तक नहीं दिया जाता है। मेरी कोशिश थी कि बेटी और दामाद में किसी तरह से सुलह हो जाए, किंतु जब मुलाकात ही नहीं होगी तो बातचीत और सुलह कैसे हो सकती है।

-पूर्णिमा राय, ऐश्वर्या की मां

जताई आपत्ति

सैन्य अधिकारियों ने कहा, परिचालन नियंत्रण में बदलाव होने से चीन सीमा पर निगरानी होगी प्रभावित, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर पीएम की अध्यक्षता वाली समिति को करना है विचार

असम राइफल्स से पूर्ण नियंत्रण छीनना ठीक नहीं : सेना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना ने असम राइफल्स के परिचालन नियंत्रण को गृह मंत्रालय के अधीन किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है। सेना का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव से चीन से लगती सीमा पर निगरानी के काम को गंभीर खतरा पैदा होगा। सेना का यह भी कहना है कि वह सीमा पर अपने सुरक्षा ढांचे में व्यापक सुधार कर रही है, ऐसे में इस बदलाव से उसके सुधार कार्यों पर भी असर पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत असम राइफल्स पर प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, जबकि उसका परिचालन नियंत्रण सेना के अधीन है।

सैन्य सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते सेना ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष अपनी चिंता को रखते हुए उससे इस मामले में हस्तक्षेप करने को भी कहा था। सेना का कहना है कि 185 साल पुरानी असम राइफल्स का परिचालन नियंत्रण गृह मंत्रालय को सौंपने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के साथ मिलाने और उसका परिचालन नियंत्रण पूरी तरह से उसके हवाले करने का प्रस्ताव तैयार किया है। पीएम की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) जल्द ही गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, 'असम राइफल्स के परिचालन नियंत्रण को सेना से हटाकर गृह मंत्रालय को सौंपे जाने से चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी को गंभीर खतरा पैदा होगा।'

बता दें कि 55,000 सैन्य बल वाली असम राइफल्स म्यांमार से लगती 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करती है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा पर सेना को परिचालन व लॉजिस्टिक मदद मुहैया कराती है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियान में भी सक्रिय रूप से शामिल होती है। सूत्रों ने बताया कि थलसेना चीन सीमा पर सैन्य ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इस स्थिति में असम राइफल्स के परिचालन नियंत्रण को गृह मंत्रालय के हवाले करने सेना की क्षमता पर असर पड़ेगा। असम राइफल्स की सहायता के चलते सेना खुद को सीमा पर निगरानी के कार्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रखती है। इसके अलावा असम राइफल्स के 70-80 फीसद जवानों को सैन्य कार्यों में तैनात किया जाता है। सेना जब अग्रिम सीमा पर लड़ती है तो असम राइफल्स सीमा की सुरक्षा के काम को सही तरीके से संभालती है।

असम राइफल्स के जवान। फाइल फोटो

अधिकारी ने बताया कि असम राइफल्स सही मायने में असली अर्धसैनिक बल है जिसने 1962 और 1971 के युद्ध समेत सभी लड़ाइयों में सक्रिय भूमिका निभाई है। असम राइफल्स में अभी 48 बटालियन हैं और उसकी ज्यादातर इकाइयों का नियंत्रण सेना के अधिकारियों के हाथों में है। सेना ने अर्ध सैनिक बल को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के प्रस्ताव के समय पर सवाल उठाए हैं, जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था गंभीर स्थिति में है।

सभी सिख विरोधी दंगा पीड़ित को मुफ्त मिलेगी 400 यूनिट बिजली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा दो साल पहले शुरू की गई 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ अब दिल्ली में रह रहे हर सिख दंगा पीड़ित को मिलेगा। पहले इसका लाभ उन्हें ही मिलता था जिनके पास सरकार के दिए फ्लैट हैं।

ऊर्जा विभाग ने संशोधित कैबिनेट नोट तैयार कर वित्त, योजना एवं विधि विभाग की राय लेने के लिए भेजा था। तीनों विभागों की राय आ गई है। ऐसे में इस योजना को अगले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इस योजना पर करीब दस करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। दिल्ली सरकार की योजना अब 400 यूनिट तक के बिजली खपत के बिल को 100 फीसद माफ करने की है। इसे वित्त वर्ष 2017-18 से लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने इस अवधि में बिजली बिलों का भुगतान किया है, उन्हें नए बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने सिक्किम के सीएम की अयोग्यता अवधि पांच साल घटाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने निर्वाचन कानून के तहत सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि रविवार को करीब पांच साल घटा दी। आयोग के इस निर्णय से उनके राज्य में होने वाले उप चुनाव में लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने तमांग को अयोग्य करार देते हुए छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। यह रोक 10 अगस्त 2018 को जेल की सजा पूरी होने के साथ शुरू हुई थी। वैसे तो यह रोक 10 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहती, लेकिन चुनाव आयोग ने रविवार को इसे घटाकर एक साल एक महीने कर दिया। इस फैसले के साथ ही 10 सितंबर को उनकी अयोग्यता अवधि समाप्त हो गई और अब वह चुनाव लड़ सकते हैं।

तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और 27 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अयोग्यता के चलते चुनाव नहीं लड़ सके थे। इस पद पर रहने के लिए शपथ लेने के छह महीने के भीतर विधानसभा सदस्य बनना आवश्यक है।

- राज्य में होने वाले उप चुनाव में प्रेम सिंह तवांग के लड़ने का रास्ता हुआ साफ
- 10 अगस्त 2018 को जेल की सजा पूरी होने के साथ शुरू हुई थी रोक

उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तमांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तमांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की अयोग्यता अवधि को कम या पूरी तरह खत्म कर सकता है। बता दें कि हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मित्रसेन यादव की अयोग्यता को आयोग ने खत्म करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी प्रदान की थी।